ऐसे इन्टर स्टेट प्राब्लम्स थे, उनका जिक्र हमने एजेंडा में नहीं किया क्योंकि हरेक का अपना-अपना दृष्टिकोण था । लेकिन बावजूद इसके यह बात तो सही है कि यह डिसप्यूट्स सार्ट आईट हो जाए तो यह देश के हित में होगा । हमारी इस सरकार का एजेंडा न होते हुए भी हमारा इस दिशा में जरुर प्रयास होगा कि ये सरकारें और उनके प्रतिनिधि बैठकर के इसको हल करें।

*242. (The questioner (Shri Karnendu Bhattacharjee) was absent, for Answer, vide col.....infra.)

*243. (The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. for Answer, vide col. ...infra.)

कारगिल तथा उसके आसपास के गांवों की सुरक्षा

***244. श्री कुशोक नवांग चम्बा स्तनजिन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल शहर तथा उसके आस-पास के गांवों के लोगों को इन क्षेत्रों में हो रही पाकिस्तानी गोलाबारी से संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) कारगिल-दरस राजमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या ज्यादा समय तक खुले रहने वाले स्पीति-किवर (एच०पी०) से होते हुए एक नई सड़क के निर्माण हेतु, जिसके लिए लद्दाख के लोगों द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली किसी भी प्रकार की गोलाबारी का समुचित जवाब देती है । हमारी तोपें प्रभावी गोलाबारी करके दुश्मन की शस्त्र-प्रणालियों को अवरूद्ध निष्प्रभावी कर देती हैं । इसके अतिरिक्त, सिविलियन आबादी को संरक्षण दिए जाने को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रशासन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आश्रय और बंकर उपलब्ध कराता है।

कारगिल-दरस राजमार्ग की सुरक्षा के लिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(क) जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान प्रभावी गोलाबारी करता है, उनके पास से स्थानीय उप-मार्ग बनाने और दीवारें खड़ी करने की योजना बनाई गई है तथा इस कार्य का एक भाग पूरा भी हो चुका है ।

(ख) किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए आपूर्ति कारवाई और अन्य प्रकार के वाहनों का आवागमन सेना द्वारा विनियमित किया जाता है ।

(ग) दरस-उम्बाला-शखु-कारगिल से गुजरते हुए एक बड़े उप-मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है । इस उप-मार्ग के छः किलोमीटर तक का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है ।

इस समय लेह से मनाली तक किसी प्रकार की नई सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कुशोक नवांग चम्बा स्तनजिन : चेयरमैन सर, पिछले एक साल से कारगिल शहर व इसके आस-पास के गांवों में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी हो रही है जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। वहां पर जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से चंद सवाल करना चाहूंगा । पहला यह है कि सरकार की ओर से कारगिल शहर और उसके पास के गांवों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ? दूसरा सवाल यह है कि सरकार की ओर से कारगिल-दरास-हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं तीसरा सवाल है लेह-श्रीनगर और लेह-मनाली हाईवे सात महीने के लिए बन्द हो जाने के कारण देश के दूसरे इलाकों से कटा रहता है । इसके लिए लद्दाख के बहुत सारे सियासती और धार्मिक संस्थाओं ने बहुत बार सैन्ट्र-गवर्नमेंट से यह अनुरोध किया कि स्पीती किवर, जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला

है जहां से रास्ता बनाया जा सकता है, उस की ओर से होते हुए एक नया रोड बनाया जाए जो लेह-मनाली, लेह-श्रीनगर हाईवे की तुलना में ज्यादा समय के लिए खुला रहेगा। सरकार ने इस बारे में क्या ठोस कदम उठाए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न अभी-अभी छेड़ा है तो इसका जवाब यों तो हमने इस स्टेटमेंट में पूरा दे दिया है। आपका प्रश्न है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? अगर आप चाहे तो मैं इसको पढ़ दूं क्योंकि हमने स्टेटमेंट सभापटल पर रख दी है। जो प्रश्न आपने पूछे हैं, उन सभी के जवाब हमने इस स्टेटमेंट में दिये हैं। जहां तक लेह-मनाली और वहां पर सड़क बनाने की बात है, इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन इस पर चर्चा एक अर्से से चल रही है और अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

डा० कर्ण सिंह : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें कुछ बातें तो बताई गई हैं लेकिन कुछ तसल्लीबख्श बात हुई नहीं है। कारगिल के लोगों को जबरदस्त तकलीफ है। एक तो ये आल्टर्नेटिव रोड़ की बात कर रहे हैं, धीमी धीमी चर्चा हो रही है। मेरा अनुरोध है इस पर सक्रिय चर्चा की जाए। क्योंकि जब तक यह दूसरी सड़क नहीं बनती तब तक यह मसला हल नहीं होना। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि कारगिल में एयर सर्विस की आवश्यकता बहुत पहले से है क्योंकि यहां सड़कें बन्द रहती हैं। लेह और कारगिल दोनों को ही इसकी बड़ी आवश्यकता है। कारगिल एयर-पोर्ट की बात बहुत पहले से चल रही है। इसका कोई तसल्लीबख्श उत्तर नहीं आया है। क्या मंत्री जी इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, माननीय सदस्य ने सड़क के बारे में जो प्रश्न पूछा है, यह बिल्कुल ही उचित प्रश्न है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चर्चा हो रही है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है तो इसके पीछे अनेक कारण हैं। जितनी जल्दी हो सके, इन परेशानियों और कारणों को दूर करके, यदि हम फैसला लेने की दिशा में जल्दी पहुंचे तो हम चाहेंगे कि वह कम हो जाए।

जहां तक कारगिल हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने और वहां से वायु सेवाओं को वहां पर पहुंचने की बात है, इस मुद्दे पर विचार बहुत लम्बे अरसे से है। अभी बीच में जो चर्चा हुई थी तो यह वायु सेवा वहां पर हो, इस पर निर्णय होने की संभावना सब को नजर आ रही है। हम चाहेंगे कि अपनी तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर जोर देकर इस सेवा को जल्दी ही शुरू किया जाए।

जहां तक कारगिल का सवाल है, यहां पर पाकिस्तान भारी मात्रा में गोला-बारी करता रहता है। इसका मुकाबला सेना अपने ढंग से कर रही है और जहां भी हमला होता है उसका इना जवाब देने की क्षमता सेना के पास है और इसकी इस्तमाली भी हमेशा होती रही है। पिछले सात-आठ महीनों में पाकिस्तान ने जो भारी मात्रा में इस इलाके में हरकतें की हैं, उसका उचित जवाब उनको सेना की ओर से दिया गया है। अब रहा सवाल शहर के लोगों की राहत का, तो मैंने उसका उत्तर तो दिया है, लकिन मैं आंकड़े रखकर भी बता दूं ताकि काम किस तरह पर चल रहा है, इसकी जानकारी हो। वहां पर बंकर वगैरह बनाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा बंकर के जरिए ही हो सकती है। कारगिल शहर की आबादी को वहां से हटाकर इस मामले का हल होने की संभावना नहीं है। इसलिए 2705 बंकर वहां पर बांधने की योजना है, जिस पर 7 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होने हैं। इसमें से एक करोड़ 42 लाख और 25 हजार रुपए अभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। यह पैसा बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से, इसमें से 20 लाख रुपया कांस्टिट्यु ऐंसी फंड से और कुछ पैसा मिनिस्ट्री आफ रुरल एरियाज की जो इम्पलीमेंट स्कीम है, इससे, इस पैसे की इंतजामी हुई है और 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार इसमें दे रही है। अभी तक 21 लाख 62 हजार करीड़ बंकर बनाने पर खर्च हो चुके हैं और यह कार्य लगातार वहां पर जारी है। इस कार्य को शीघ्र ही समाप्त करके शहर के लोगों को जो सुरक्षा देने की आवश्यकता है, उसकी इंतजामी हो चुकी है।

श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मंत्री जी ने सड़क के बारे में जो उत्तर दिया है, उस संदर्भ में मुझे पूछना है कि क्या रक्षा मंत्रालय इस बात को आवश्यक मानता है कि नई सड़क बनाई जाए, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है वह यह है कि वहां वर्ष में आठ महीने, नौ महीने तक जो सड़क है, वह बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में नई सड़क बनाए जाने की बारे में चर्चा कई बार हुई लेकिन क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इसको अन्यावश्यक मानता है ? अगर मानता है तो उसने इस बारे में क्या किया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय प्रतिरक्षा मंत्रालय इस सड़क की आवश्यकता को जरूर महसूस करता और शायद अत्यधिक महसूस करता है । लेकिन जब पैसे का प्रश्न आता है तब हमारे सामने प्राथमिकता की बात आ जाती है । आज जम्मू-कश्मीर के इलाके में और विशेषकर उन इलाकों में जहां पर वहां के लोगों को कई बार हमलों का सामना करना पड़ रहा है, उन इलाकों में सड़कें बनाने को प्राथमिकता दी गई है । जो भी सड़कों के लिए आबिटन हुआ है वह उन इलाकों में इस वक्त जा रहा है । इसलिए प्रश्न प्राथमिकता का है । जहां भारी संघर्ष है, उस इलाके में सड़कों को प्राथमिकता देना हमारा संकल्प है ।

*245. [The questioner (Shri S. Agniraj) was absent. For Answer, vide col.....infra]

*246. [The questioner (Shri Krishna Kumar Birla) was absent. For Answer, vide col.....infra]

*247. [The questioner (Shri Parag Chalika) was absent. For Answer, vide col.....infra]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश द्वारा धनराशि का उपयोग

***248. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना और अन्य उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) उक्त धनराशियों का जिला-वार और कार्यक्रम-वार कितना-कितना कम उपयोग किया गया अथवा पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया;

(ग) सरकार ने उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशियों का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ; और

(घ) राज्य के विदिशा जिले में प्रति व्यक्ति उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आबागौडा पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों यथा, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना के अन्तर्गत आबंटित, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त राशि के जिलावार ब्यौरे अनुपत्र में दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट 185, अनुपत्र सं. 47]

(ग) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने एक बृहत् निगरानी व्यवस्था बनाई है, जिसमें मासिक प्रगति रिपोर्टें, वित्तीय रिटर्नें/लेखा-परीक्षण रिपोर्टें, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षणें, क्षेत्रीय अधिकारियों की योजना, विभिन्न समितियां यथा, संसदीय परामर्शदात्री/स्थायी समिति और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशकों तथा ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों की बैठकें शामिल हैं ।

(घ) वर्ष 1991 की आबादी के आधार पर 1998-99 में ग्रामीन क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए विदिशा जिले में प्रति व्यक्ति की जाने वाली राशि लगभग 73.00 रुपये (मांग पर आधारित सुनिश्चित रोजगार योजना को छोड़ कर) है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जो जो स्टेटमेंट